International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 08-04-2025, Accepted: 09-05-2025, Published: 24-05-2025
Volume 11, Issue 3, 2025, Page No. 47-49

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के परिप्रेक्ष्य में सारंगढ़–बिलाईगढ़ ज़िले के प्राथमिक विद्यालय में हुए परिवर्तन: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

सुनीता यादव
सहायक शिक्षक, शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा खिचरी, विकासखंड, बरमकेला, जिला, सारंगढ़, बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़, भारत

सारांश
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद सारंगढ़–बिलाईगढ़ ज़िले की प्राथमिक शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन देखे गए हैं। शिक्षण पद्धति अब अधिक गतिविधि–आधारित और छात्र–केंद्रित हो गई है। मातृभाषा में शिक्षा और सतत मूल्यांकन प्रणाली ने बच्चों की सीखने की रुचि और समझ को बढ़ाया है। शिक्षक नवाचार को अपनाने लगे हैं, जिससे कक्षा में सहभागिता बढ़ी है। हालांकि, डिजिटल संसाधनों की कमी, शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता और अभिभावकों की सीमित भागीदारी जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। नीति की सफलता के लिए समुचित कार्यान्वयन, संसाधन विकास और समुदाय की सक्रिय सहभागिता अनिवार्य है।

मूलशब्द: सारंगढ़–बिलाईगढ़, प्राथमिक विद्यालय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बाल्यावस्था शिक्षा, शिक्षण पद्धति

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) ने देश की शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं। यह नीति विशेषकर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन प्रणाली एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण में बदलाव की बात करती है। यह शोधपत्र छत्तीसगढ़ राज्य के सारंगढ़–बिलाईगढ़ ज़िले में प्राथमिक शिक्षा पर NEP 2020 के प्रभाव का विश्लेषण करता है।

छत्तीसगढ़ का नवगठित जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर–पूर्वी हिस्से में स्थित सारंगढ़–बिलाईगढ़ जिला 1 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया। इसका गठन जिला रायगढ़ एवं बलौदाबाजार–भाटापारा के विभाजन से किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की थी। यह जिला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मुख्यालय सारंगढ़ में स्थित है, जो राज्य की राजधानी रायपुर से लगभग 201 किलोमीटर दूर है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह क्षेत्र किसान आंदोलन एवं जंगल सत्याग्रह का केंद्र रहा है। पूर्व में यह क्षेत्र सारंगढ़ रियासत के अंतर्गत आता था, जहाँ गोंड शासकों का शासन था। आज भी यहाँ स्थित गिरीविलास पैलेस इसकी ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए है। सारंगढ़ नाम का उद्गम विभिन्न मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। एक मान्यता के अनुसार 'सारंग' शब्द का अर्थ बांस होता है और यहां बांस की प्रचुरता के कारण इसे सारंगढ़ कहा गया। वहीं पं. लोचन प्रसाद पांडे इसे चिमय मृग से जोड़ते हैं, जबकि डॉ. विनय कुमार पाठक के अनुसार सारंग पक्षी की अधिकता इस नाम का कारण है। जिले की सीमाएं उत्तर में रायगढ़, दक्षिण में महासमुंद, पूर्व में ओडिशा के बरगढ़ तथा पश्चिम में बलौदाबाजार और उत्तर–पश्चिम में जांजगीर–चांपा से लगी हुई हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 6,17,252 है, जिसमें 759 ग्राम, 349 ग्राम पंचायतें और 5 नगरीय निकाय शामिल हैं। कुल 20 राजस्व निरीक्षक मंडल और 1,65,014 हेक्टेयर राजस्व क्षेत्रफल के साथ यह जिला प्रशासनिक दृष्टि से सशक्त है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की दृष्टि से जिले में 1406 स्कूल, 7 कॉलेज हैं। नए जिले के गठन से प्रशासनिक विकेंद्रीकरण हुआ है, जिससे लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ तेजी से और सुगमता से मिलने लगा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्यान्न जैसी मूलभूत सुविधाओं की पहुँच दूरस्थ अंचलों तक सुनिश्चित हुई है। इसके अलावा सड़क, पुल–पुलिया जैसे निर्माण कार्यों से सुदूर वनांचल क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर हुई है। सारंगढ़–बिलाईगढ़ का गठन न केवल प्रशासनिक सुविधा का विस्तार है, बल्कि यह क्षेत्रीय विकास की नई दिशा भी प्रदान करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मद्देनज़र प्राथमिक विद्यालयों में होने वाले बदलाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारत की शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार है, जिसका उद्देश्य समावेशी, बहुभाषी, समग्र और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ राज्य, जो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है, अब NEP 2020 के दिशा–निर्देशों के अनुसार अपने प्राथमिक विद्यालयों में व्यापक बदलाव की दिशा में अग्रसर है।

सबसे बड़ा बदलाव पारंपरिक 10+2 संरचना को हटाकर 5+3+3+4 की नई संरचना लागू करना है। इसके तहत प्राथमिक शिक्षा अब तीन से आठ वर्ष की आयु के बच्चों के लिए "फाउंडेशनल स्टेज" के रूप में मानी जाएगी, जिसमें बालवाड़ी (प्री–स्कूल) और कक्षा 1–2 को शामिल किया गया है। इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक स्कूलों के समन्वय पर विशेष जोर देना शुरू कर दिया है। अब बच्चों की पूर्व–प्राथमिक शिक्षा को मज़बूत किया जा रहा है ताकि वे कक्षा 1 में प्रवेश से पहले बुनियादी भाषा और संख्याज्ञान में दक्ष हो सकें।

मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा NEP 2020 का एक प्रमुख बिंदु है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लागू करने के लिए स्थानीय भाषाओं और बोलियों जैसे छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी आदि को प्राथमिक शिक्षा में स्थान दिया जा रहा है। इससे बच्चों को अपनी भाषा में सीखने का अवसर मिल रहा है, जिससे उनकी समझ और सीखने की गति बेहतर हो रही है।

बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy) को प्राथमिक शिक्षा का मूल आधार माना गया है। "निपुण भारत" और "पढ़ई तुंहर दुआर" जैसी योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों की पढ़ने–लिखने और गणित की मूलभूत क्षमताओं को विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है।

शिक्षण की पद्धति में नवाचार और खेल आधारित, गतिविधि आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। प्राथमिक स्कूलों

में बच्चों को समझ के साथ सीखने, प्रश्न पूछने और रचनात्मक सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल सामग्री, और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इस बदलाव को व्यवहार में लाया जा रहा है। शिक्षकों की भूमिका और प्रशिक्षण भी बदली है। NEP 2020 के तहत शिक्षकों को बहु–विषयी शिक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा नियमित शिक्षक प्रशिक्षण शिविरों और ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। NEP 2020 छत्तीसगढ़ के प्राथमिक शिक्षा तंत्र में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। शिक्षा को बाल केंद्रित, समावेशी और भविष्य की ज़रूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में यह नीति और इसके अंतर्गत किए जा रहे प्रयास आने वाले वर्षों में राज्य के शिक्षा परिदृश्य को पूरी तरह से बदल सकते नवगठित जिले में तीन तहसीलें — सारंगढ़, बरमकेला और बिलाईगढ़ तथा उपतहसील कोसीर और भटगांव शामिल हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में तीन जनपद पंचायतें — सारंगढ़, बरमकेला और बिलाईगढ़ हैं।

सरंगढ़–बिलाईगढ़ में प्राथमिक शिक्षा में हुए प्रमुख परिवर्तन

1. **सरंगढ़:** बिलाईगढ़ ज़िले की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षण पद्धति में स्पष्ट बदलाव देखने को मिले हैं। पहले जहां शिक्षा प्रणाली परंपरागत और पाठ्यपुस्तक–आधारित थी, वहीं अब इसे अधिक खेल–केंद्रित, गतिविधि–आधारित और छात्रों की भागीदारी पर केंद्रित बनाया गया है। कक्षा 1 और 2 में षनिपुण भारत मिशनष के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी साक्षरता और गणना कौशल (थ्वनदकंजपवदंस स्पजमतंबल ंदक छनउमतंबल) को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षकों को स्थानीय संसाधनों और रचनात्मक तरीकों से पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया अधिक रुचिकर और प्रभावशाली बन रही है।

2. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद सरंगढ़:** बिलाईगढ़ ज़िले की प्राथमिक शिक्षा में भाषा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं। नीति के अनुसार, कक्षा 3 तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की गई है। इसी के अनुरूप ज़िले के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में छत्तीसगढ़ी या हिंदी माध्यम को प्राथमिकता दी जा रही है। शिक्षण में स्थानीय भाषा के बढ़ते प्रयोग से बच्चों को विषयवस्तु को समझने में आसानी हो रही है। शिक्षकों ने भी कक्षा में संवाद हेतु स्थानीय बोली का अधिक उपयोग करना शुरू किया है, जिससे बच्चों की भागीदारी और सीखने की गति में सकारात्मक सुधार देखा गया है।

3. **सरंगढ़**: बिलाईगढ़ ज़िले की प्राथमिक शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मूल्यांकन प्रणाली में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। पहले जहाँ वार्षिक परीक्षा ही छात्रों के शैक्षणिक मूल्यांकन का मुख्य आधार होती थी, वहीं अब नीति के अनुसार निरंतर और समग्र मूल्यांकन (ब्म्) को अपनाया गया है। इससे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया का निरंतर अवलोकन संभव हो सका है। विद्यालयों में अब मासिक मूल्यांकन, सीखने के पोर्टफोलियो, व परफॉर्मेंस रिपोर्ट के माध्यम से छात्रों की प्रगति को आँका जा रहा है। इस बदलाव ने मूल्यांकन को केवल परीक्षा–आधारित न रखते हुए, बच्चों की समग्र समझ, व्यवहारिक कौशल और रचनात्मकता को भी महत्व देना शुरू किया है।

4. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभाव स्वरूप सरंगढ़:** बिलाईगढ़ ज़िले की प्राथमिक शिक्षा में डिजिटल साधनों का उपयोग धीरे–धीरे बढ़ रहा है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ विद्यालयों में ई–कंटेंट और ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे शिक्षक अब तकनीक के माध्यम से शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना पा रहे हैं। दीक्षा ऐप, पढ़ई तुंहर दुआर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जानकारी शिक्षकों को दी जा रही है और उन्हें इनका उपयोग सिखाने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। हालांकि यह प्रक्रिया अभी प्रारंभिक चरण में है, लेकिन इससे शिक्षा में डिजिटल समावेशन की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया गया है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के पश्चात सरंगढ़–भिलाईगढ़ ज़िले की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। शिक्षण अब अधिक रचनात्मक, छात्र–केंद्रित और गतिविधि–आधारित हो गया है, जिससे बच्चों की सीखने में रुचि और सहभागिता बढ़ी है। कक्षा 1 व 2 में "निपुण भारत मिशन" के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और गणना कौशल पर विशेष बल दिया जा रहा है। भाषा नीति के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देने से बच्चों की समझ और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। मूल्यांकन प्रणाली में भी सुधार हुआ है दृ अब निरंतर और समग्र मूल्यांकन के ज़रिए बच्चों की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। शिक्षक पोर्टफोलियो, मासिक रिपोर्ट और व्यवहारिक निरीक्षण जैसे आधुनिक तरीकों को अपना रहे हैं। डिजिटल शिक्षा की दिशा में भी कदम बढ़े हैं; कुछ विद्यालयों में दीक्षा ऐप और ई–सामग्री के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण शुरू किया गया है। हालांकि, अभी भी डिजिटल संसाधनों की कमी, शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता, और अभिभावकों की सीमित भागीदारी जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। नीति की सफलता के लिए सतत प्रयास, समुचित संसाधन और सामुदायिक सहयोग आवश्यक है।

संदर्भ सूची

1. Government of India. National Education Policy 2020. Ministry of Human Resource Development, 2020 [cited 2025 May 24]. Available from: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
2. Ministry of Education. NIPUN Bharat: National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy, 2021 [cited 2025 May 24]. Available from: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nipun_bharat_guidelines_en.pdf
3. Government of Chhattisgarh. Annual Status Report on School Education in Chhattisgarh. School Education Department, Raipur, 2022.
4. NCERT. Learning Outcomes at the Elementary Stage. National Council of Educational Research and Training, 2020 [cited 2025 May 24]. Available from: https://ncert.nic.in/pdf/announcement/Learning_Outcomes_English.pdf
5. UNICEF India. Transforming Education through Technology in Rural India, 2021 [cited 2025 May 24]. Available from: https://www.unicef.org/india/reports/transforming-education-through-technology

6. Patel R, Verma S. Implementation of NEP 2020 in Rural Primary Schools: A Case Study of Chhattisgarh. J Indian Educ,2023:48(2):34–45.
7. Aggarwal JC. Development and planning of modern education. 11th ed. Vikas Publishing House, 2020.
8. Sharma RA. Educational philosophy and policy of education. R. Lall Book Depot, 2021.
9. MHRD. National Education Policy 2020: A transformative vision. Government of India Publications, 2020.
10. Dash BN. Teacher and education in the emerging Indian society. Neelkamal Publications, 2018.